ses including the non-viable ones at periodic intervals both at the level of the administrative ministries and the bureau of Public Enterprises and remedial steps considered necessary are taken to improve the performance depending on the circumstances of each case.

The names of, and the loss incurred by loss making enterprises are available in the Public Enterprises Surveys placed on the Table of Rajya Sabha every year.

Construction of Board of Directors for the Nationalised Banks

2422. SHRI NAND KISHORE BHATT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) by when the new Board of Directors of all the nationalised banks are likely to be constituted; and

(b) whether due representation will be given to the employees and officers of the respective banks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Boards of Directors of nationalised banks have not been dissolved. However, in terms of provisions of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Schemes, 1970 and 1980, such of those non-official Directors who had completed three years as Directors had been notified as having ceased to hold office from the date they completed three years as Directors. Resultant vacancies have not yet been filled. The process of selecting suitable persons for such vacancies is under way.

(b) Appointment of Directors on the Boards of nationalised banks is governed by the provisions of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Schemes, 1970 and 1980. The Schemes provide for appointment of one Director from among the workmen employees and one Director from among the non-workmen employees of the nationalised banks.

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ

2343. **श्री सुशील चन्द मोहन्ता :**

श्री राम नरेश कुशवाहा:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक व्यापार निगम ने अभ्रक निर्माताओं के साथ एक के बाद दूसरा समझौता करके कमीशन के रूप में 1 करोड 3 लाख रुपये का युद्ध लाभ अर्जित किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभ्रक व्यापार निगम (मिटकों) ने वार्षिक आय, सभी व्यावसायिक समझौतों तथा उपरोक्त कमीशन को मिला कर मात्र 42 लाख रुपये का लाभ दिखाया है, और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर हां हों तो क्या सरकार इस मामले में जांच करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं । 1983–84 के दौरान निगम ने बैक-टू-बैक प्रबंधों पर सेवा प्रभारों के रूप मे 16.57 लाख रु० की प्राप्ति सहित अपने सभी कार्यक्रमों पर 191.98 लाख रु० का समग्र लाभ अर्जित किया । इस अवधि के दौरान इसका विकल लाभ 52.25 लाख रु० था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम

2424. **श्री राम नरेश कुशवाहा :**

श्री सुशील चन्द मोहन्ता :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक व्यापार निगम की कुल कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि निगम में अधिकारी आवश्यकता से अधिक हैं; यदि हां, तो सरकार इस समस्या पर किस प्रकार काबू पाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पटसन स्थित इसके प्रधान कार्यालय सहित भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की शाखाओं/फैक्टरियों की कुल संख्या ग्यारह है ।

(ख) जी नहीं ।

अभ्रक सहकारी फैक्टरी का लगाया जाना

2315 **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमजोर वर्गों के अभ्रक डीलरों और बेरोजगार मजदूरों को रोजी रोटी कमाने के लिए अभ्रक सहकारी फैक्टरी लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गये है ; और

(ख) यदि इस दिशा मे कोई कदम नहीं उठाये गए है तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) इस समय भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० को अभ्रक सप्लाई करने वाली संसाधकों तथा व्यापारियों की एक सहकारी समिति है । कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले माइक डीलरों को जीविका प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० उनसे अपनी 90% से भी अधिक खरीदारियां करता है, जिसमें उपर्युक्त अभ्रक सहकारी समिति भी शामिल है । मिटकों ने हाल में एक "अति कमजोर को सहायता" योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत अभ्रक संसाधक अभ्रक की छोटी मात्राएं भी सप्लाई कर सकते हैं । बेरोजगार कामगार भी अपनी सहकारिता समितियां बना सकते हैं अथवा व्यक्तिगत रूप से भी मिटकों को सप्लाई कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, मिटकों ने 945 कामगारों को रोजगार देते हुए संसाधित अभ्रक के लिए सात फैक्टरियों/एककों की स्थापना की है । मिटको ने अपने कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने की दृष्टि से उनके लिए नियमित वेतन मान भी प्रारंभ किए हैं ।

Central Public Sector Industries in Basti District in U. P.

2426. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of Central public sector industries located in Basti district of Uttar Pradesh; and

(b) what is the number of persons engaged category-wise in these industries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARY): (a) and (b) The details are being collected and a statement will be placed on the Table of the House.

Political Donations

2427. SHRI RAMCHADRA BHARADWAJ:

SHRI J. P. GOYAL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether public units give donations to political parties;

(b) if so, what are the guidelines issued by Government in this regard;

(c) whether the Election Commission desired that Government should put specific injunction against political donations by public undertakings; and